लिये 22 परियोजनाओं द्वारा भारतीय वित्तीय संस्थानों से लगभग 16000 करोड़ रुपये का ऋण सुनिश्चित किया गया है जिनमें से अभी तक 9 परियोजनाओं ने वित्तीय समापन प्राप्त कर लिया है।

(ङ) वर्ष 1997-98 के लिये निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में विद्युत परियोजनाओं के लिये 3239 मे०वा० क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसकी तुलना में उपलब्धियां 3283.3 मे०वा० थी।

टिहरी बांध की लागत में वृद्धि होना

3914. **श्री मनोहर कांत ध्यानी:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि टिहरी पन बिजली परियोजना का आकार वर्ष 1987 के 1370.86 करोड़ रुपये से बढ़कर 4570 करोड़ रुपए हो गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सन 2002 तक इस राशि के 6000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाने की संभावना है;

(ग) इन चार वर्षों में प्रति वर्ष कितनी धनराशि व्यय किये जाने का विचार है; और

(घ) क्या इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु हर संभव उपाय किये गये है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) और (ख) दिसम्बर, 1997 के मूल्य स्तर पर परियोजना की अनुमानित लागत 4657.23 करोड़ रुपए है। परियोजना की अनुमानित लागत मार्च, 2002 में चालू किये जाने के कार्यक्रम के साथ कार्यान्वयन के दौरान सामान्य मूल्य वृद्धि के अध्याधीन होगी।

(ग) 1642.45 करोड़ रुपए की राशि मार्च, 1998 तक खर्च की जा चुकी है। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा यथा प्रक्षिप्त किये गये के अनुसार मार्च, 2002 में चालू किये जाने के कार्यक्रम के साथ 4657.23 करोड़ रुपए के संशोधित लागत अनुमानों के आधार पर निधियों की वर्ष-वार आवश्यकता निम्नलिखित है:—

वर्ष	निधियों की प्रक्षिप्त आवश्यकता (करोड़ रुपए में)
1998-99	530.00
1999-2000	714.46
2000-01	750.00
2001-02	750.00
2002-03 (स्पिलओवर व्यय)	270.32
जोड़	3014.78

(घ) जी, हां। परियोजना के प्रमुख सिविल निर्माण कार्यों की निर्माण संबंधी गतिविधियों प्रगति पर हैं। उत्पादन उपस्कर के "आर्डर" दिये जा चुके हैं। मार्च, 2002 तक परियोजना को पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिये परियोजना की निर्माण संबंधी गतिविधियों के लिये वर्ष-वार लक्ष्य तैयार किये गये है।

टिहरी बांध की झील के डूब क्षेत्र में आने वाले संभावित गांव

3915. **श्री मनोहर कांत ध्यानी:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि टिहरी बांध की झील से लगभग नब्बे गांवों के पूर्णतः या अंशतः डूबने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो अंशतः डूबने वाले संभावित गांवों की सही-सही संख्या क्या है;

(ग) पूर्णतः डूबने वाले संभावित गांवों की सही-सही संख्या क्या है;

(घ) पूर्णतः डूबने वाले गांवों में रहने वाले परिवारों की संख्या क्या है; और

(ङ) अब तक कितने गांवों और परिवारों का पुनर्वास किया जा चुका है?

विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) और (ग) टिहरी बांध के जलाशय से कुल 96 बांध डूब जाएगें जिसमें से 22 गांव पूर्णतः डूबेगें और 74 गांव अशतः डूब जाएगें।

(घ) जलमग्नता के कारण कुल मिलकर 4226 परिवार (22 पूर्ण जलमग्नता वाले गांवों से संबंधित 2301 परिवार समेत) पूर्णतः प्रभावित होगे।

(ङ) टिहरी हाईड्रो डवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा पूर्णतः प्रभावित ग्रामीण परिवारों का पुनर्वास दो चरणों मे किया जा रहा है। काफर बांध निर्माण के कारण होने वाली जलमग्नता से संबंधित चरण-I में 15 पूर्णतः जलमग्न हुये गांवों के 1381 परिवारों का पुनर्वास शामिल है। मुख्य बांध द्वारा होने वाली जलमग्नता से संबंधति चरण-II के पुनर्वास में शेष पूर्ण जलमग्न हुये गांवों और 74 आंशिक जलमग्न हुये गांवों को सम्मिलित किया जाएगा, जिसमें शेष 2845 पूर्णतः प्रभावित परिवार शामिल है। चरण I में सभी पूर्णतः प्रभावित ग्रामीण परिवारों का पुनर्वास किया गया है। चरण-II कार्यक्रम के तहत 435 पूर्णतःप्रभावित परिवारों को अभी तक पुनर्वास किया गया है।

Clearance of Fast Track Power Projects

3916. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of POWER be pleased to state

(a) whether Government have recently cleared certain fast track power projects involving considerable F.D.I. and if so, the details thereof;

(b) the details of the projects which are still pending and by when these are likely to be cleared; and

(c) whether Government have formulated any transparent rules for project approval and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF POWER (SHRI R. KUMARAMANGALAM): (a) to (c) The Government of India in 1994 identified 8 Projects for extending its counter-guarantee. Out of these, counter-guarantee has already been issued to the jegurupadu Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) (216 MW) of M/s. GVK Industries in Andhra Pradesh and Dabhol CCGT (Phase I) (740 MW) of M/s Enron Power Company in Mahrashtra, M/s Spectrum Power Generation Ltd. withdrew their request for counter-guarantee for the Godavari CCGT (208 MW) in Andhra Pradesh. In the case of the IB Valley Thermal Power Project (Unit 3 & 4) of M/s AES Ib Valley Power Corporation in Orissa, Government of India's counter-guarantee had been accorded to the project. Subsequently, the State Government re-negotiated the project parameters with M/s AES Ib Valley Power Corporation and they were allocated Units 5 & 6 (now renamed as Unit A & B) of the Ib Valley Thermal Power Project, Fresh techno-economc clearanace of Central Electricity Authority (CEA) is necessary for this project on account of the revised project parameters.

On 16.5.1998, the Government approved extension of counter-guarantee in the case of the Visakhapatnam Thermal Power Project (1040 MW) of M/s Hinduja National Power Company Limited (HNPCL) in Andhra Pradesh, Bhadravati Thermal Power Project (1057 MW) of M/s Central India Power Company (CIPCO) in Maharashtra and 250 MW single unit lignite based Neyveli Thermal Power Project of M/s ST-CMS Electric Company in Tamil Nadu, through a revised procedure. It has inter-alia been decided that counter-guarantee will be given only in the event of termination and will be limited to the outstanding foreign debt only.

Financial Assistance to Kota Thermal Power Station

3917. DR. MAHESH CHANDRA SHARMA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether any proposal has been received from Government of Rajasthan in regard to Kota Thermal Power Station Stage IV;

(b) whether the techno-economic clearance has been accorded for the project from the CEA;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) whether this project is under consideration of Government for financial assistance from external agencies?

THE MINISTER OF POWER (SHRI R. KUMARAMANGALAM): (a) to (c) A proposal to set up Kota Thermal